जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार को होने वाले भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास ''वायु शक्ति-2026'' की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार शाम जैसलमेर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम जैसलमेर में करेंगी। शुक्रवार सुबह वे वायुसेना स्टेशन जाएंगी और शाम को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगी, जहां वायु शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य आयोजन होगा।

सिलीगुड़ी में भूकम्प के झटके

सिलीगुड़ी, 26 फरवरी। सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल के कई इलाकों में गुरुवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर से पहले आए इस कंपन से सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के विस्तृत क्षेत्रों में दहशत फैल गई। झटकों का असर कोलकाता तक महसूस किया गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया।

- **तीव्रता 4.6 दर्ज हुई, कोई जनहानि नहीं।**

मौसम विभाग के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 दर्ज की गई। इसका केंद्र सिक्किम में था और झटके सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर महसूस किए गए।

पर्यटन सीजन होने के कारण दार्जिलिंग और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन और मौसम विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

प्रधानमंत्री अजमेर में 21 हजार 800 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे

मोदी बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरु करेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे

जयपुर, 26 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार (28 फरवरी) को राजस्थान के अजमेर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री केन्द्र एवं राज्य सरकार की 16 हजार 686 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे।

एचपीवी टीकाकरण अभियान की पहल सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य किशोरियों का प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है।

- **प्रधानमंत्री मोदी राज्य के शहरी विकास, पेयजल, सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा व औद्योगिक क्षेत्र की 16 हजार 800 करोड़ रूपए की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।**
- **प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 5 हजार जवान कार्यक्रम स्थल व आसपास तैनात रहेंगे। सभा स्थल की निगरानी आधुनिक तकनीक के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए की जाएगी।**

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढ ांचे समेत, विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 16 हजार 686 करोड़ रुपये की लागत की 43 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

इन परियोजनाओं में बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन, जयपुर में सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक एलीवेटेड रोड, जोधपुर शहर में 4 लेन एलीवेटेड रोड का शिलान्यास भी करेंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में चयनित 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे।

करीब पांच हजार पुलिस और सुरक्षा जवान पूरे कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाली देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा एजेंसी के कमांडो भी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। सभा स्थल की निगरानी आधुनिक तकनीक के साथ-साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी की जा रही है। आसमान से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे।

सुनेत्रा पवार बनीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुंबई, 26 फरवरी। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय मुंबई के वर्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

इस बैठक में राकांपा (एपी) के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पेश किया। बैठक में उपस्थित सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव को सहमति दी। इसके बाद पटेल ने सुनेत्रा पवार को राकांपा (एपी) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। राकांपा (अजित पवार) प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित, सभी नेताओं ने सुनेत्रा पवार का स्वागत किया। सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए पार्थ पवार को नामित किया जाएगा। पार्थ अजित पवार और सुनेत्रा के बड़े बेटे हैं।

- **सुनेत्रा ने पूरी तरह से अपने स्व.पति अजीत पवार की विरासत संभाल ली है**
- **इससे पहले उन्हें अजीत पवार के रिक्त उपमुख्यमंत्री पद पर भी नियुक्त किया गया था।**

इस मौके पर सुनेत्रा पवार ने कहा कि वे बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही हैं। अजित पवार इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए रात-दिन काम करते थे। वे हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। अब वे नहीं हैं तो उनकी जिम्मेदारी उन पर हैं।

कैनडा के प्र.मंत्री कार्नी आज भारत में

नई दिल्ली, 26 फरवरी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और नई साझेदारियों की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से कार्नी की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

प्रधानमंत्री कार्नी 01 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे तथा 02 मार्च को मोदी एवं कार्नी हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत-कैनडा रणनीतिक साझेदारी के अलग-अलग क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जो कनानास्किस (जून 2025) और जोहान्सबर्ग (नवंबर 2025) में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी। वे व्यापार निवेश ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिजों कृषि शिक्षा अनुसंधान और नवाचार जैसे खास स्तंभों पर सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ शिकंजा कसा

ईडी ने एयर सैल मैक्सिस तथा आईएनएस मीडिया केस में यह कार्यवाही की

नई दिल्ली, 26 फरवरी। राऊज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ प्राप्त अभियोजन स्वीकृति आदेश दाखिल कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से यह आदेश अदालत में प्रस्तुत किया गया।

ईडी के अनुसार, एयरसेल-मैक्सिस मामले में उसने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच सीबीआई द्वारा 9 अक्टूबर 2011 को दर्ज एफआइआर के आधार पर शुरू की थी। एजेंसी का आरोप है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी. चिदंबरम ने 20 मार्च 2006 को एयरसेल-मैक्सिस को विदेशी निवेश स्वीकृति प्रदान की, जबकि प्रस्तावित निवेश राशि 600 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण इसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अधिकार क्षेत्र में आती थी।ईडी ने कहा कि जांच में यह सामने आया कि इस स्वीकृति के बदले अवैध लाभ लिया गया और 1.16 करोड़ रुपये की राशि कंपनियों के माध्यम से प्राप्त हुई। इस राशि को 23 सितंबर 2017 को अस्थायी रूप से अटैच किया गया था। एजेंसी ने बताया कि इस मामले में 13 जून 2018 को अभियोजन शिकायत व 25 अक्टूबर 2018 को पूरक शिकायत विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल की गई थी, जिसमें पी. चिदंबरम को आरोपी बनाया गया।

- **ईडी का आरोप है कि पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए एयर सैल मैक्सिस को विदेशी निवेश की स्वीकृति दी थी जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी।**

पंजाब विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। ऐसा लगता है कि भाजपा में, 2024 के लोकसभा चुनावों में मिले 18.5 प्रतिशत वोट शेयर से आत्मविश्वास पैदा हुआ है, जो उसे पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' और ''पूर्वांचल सम्मान'' जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ, भाजपा की रणनीति गैर-पंजाबी प्रवासी वोट बैंक को एकजुट करने पर केन्द्रित रही है, जो लुधियाना जैसे शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में एक प्रमुख वोट ब्लॉक बनाता है। गृह मंत्री 14 मार्च को मोगा में होने वाली ''बदलाव रैली'' में प्रवासी वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं पार्टी नेताओं में एसएडी के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जिसमें एक पक्ष का मानना है कि इससे पूर्व एसएडी सरकारों से जुड़ा गैंगस्टरवाद और ड्रग्स की समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि, पूर्व कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह सहित, दूसरे पक्ष का कहना है कि एसएडी के साथ रिश्तों को फिर से जीवित करना भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बहु-कोणीय मुकाबलों के बीच यह पार्टी को लाभ पहुंचा सकता है। कांग्रेस, आप, भाजपा और एसएडी के अलावा, छोटे दल और बिखरे हुए समूह, जैसे अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और एसएडी (अमृतसर) भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया गया है, जिसे वह संविधानिक नैतिकता और मूल संरचना सिद्धांत को कायम रखने में निभाती है।

भारत का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलकर संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

अनिल अंबानी के मुंबई ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की

यह कार्यवाही बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में की गई है

नई दिल्ली, 26 फरवरी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा ऋण मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास और कार्यालय में तलाशी ली। यह कार्रवाई 2,220 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई है। सीबीआई के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा की 24 फरवरी 2026 की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसके प्रमोटर एवं पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंक से लिए गए ऋण को संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन दिखाकर डायवर्ट किया और दुरुपयोग किया। कंपनी के खातों में हेरफेर किया गया और अनियमितताओं को छिपाया गया। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। सीबीआई के मुताबिक, यह खाता वर्ष 2017 में ही एनपीए घोषित कर दिया गया था। हालांकि, अनिल अंबानी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद खाते को धोखाधड़ी घोषित करने पर रोक लगी थी। यह रोक 23 फरवरी 2026 को हटने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई ने तुरंत मामला दर्ज किया। जांच एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 11 बैंकों के कंसोर्टियम से जुड़े एक अलग मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा उस कंसोर्टियम का हिस्सा नहीं था। यह ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा, तत्कालीन विजया बैंक और देना बैंक से लिया गया था, जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुके हैं। मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के आवास और रिलायंस कम्युनिकेशंस के पंजीकृत कार्यालयों पर तलाशी ली।

- **सीबीआई के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर अनिल अंबानी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने फर्जी लेनदेन दिखाकर ऋण का दुरुपयोग किया था।**

जल जीवन मिशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बरामद हुए थे। बताया जाता है कि पदम चन्द जैन अन्य आरोपियों की ओर से रिश्वत मांगता और रिश्वत राशि प्राप्त करता था। इन आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है। याचिकाकर्ता ठेका फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के कर्मचारी हैं। उन्होंने न तो रिश्वत राशि को लेकर कोई बात की है और न ही कोई काम किया है। वहीं उनका एफआईआर में नाम भी नहीं है। जलदाय विभाग और ठेका फर्म के बीच सिविल प्रकृति का विवाद होने के चलते निचली अदालत में सिविल केस भी दर्ज कराए गए हैं। याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज होने के दो साल बाद गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की अपने फर्म मालिकों से हुई बातचीत के तथ्यों से साबित है कि अपराध में उनकी भूमिका भी थी। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

'नरेन्द्र आप दोस्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होता है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्त नरेन्द्र, मैं आपकी यात्रा से खासा प्रभावित हूं। आप इज़राइल के एक महान दोस्त हैं और विश्व मंच पर एक महान नेता हैं, नरेन्द्र, आप दोस्त से बढ़कर हैं। आप एक भाई हैं।''

दोनों नेताओं के बीच की व्यक्तिगत कैमिस्ट्री इज़राइल में बहुत प्रचारित की जा रही है, और यह कनेसट में भी स्पष्ट रूप से देखी गई, जहाँ दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और सबने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। गले मिलते हुए और सांसदों व दर्शकों का खड़ा होकर ताली बजाने का दृश्य अद्भूत था। नेतन्याहू ने कहा, ''आज एयरपोर्ट पर हम एक-दूसरे से गले मिले। इसे मोदी हग कहा जाता है। मैं यहां हर कनेसट सदस्य की तरफ से उन्हें गले लगाने आया हूं। यह हमारे बीच की गर्मजोशी का प्रतीक है।''

इज़राइली प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो साझा करते हुए मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''मेरे कनेसट संबोधन के बाद, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैं एक प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी की दुनिया में की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है।''

एनसीईआरटी की किताब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईमानदारी पर सवाल उठाना नहीं था। परिषद ने कहा कि अध्याय का उद्देश्य संस्थागत चुनौतियों पर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना था, न कि समग्र रूप से न्याय प्रणाली की ईमानदारी पर सवाल उठाना। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अधिक संतुलन और संदर्भ की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन पर विचार किया जाएगा।

यह घटना एक व्यापक बहस को फिर से खोल देती है कि नागरिक शिक्षा को संस्थागत कमियों को कैसे संबोधित करना चाहिए। एक ओर, प्रणालीगत मुद्दों जैसे मामलों के लंबित होने और न्यायिक रिक्तियों की पारदर्शिता नागरिकता की जानकारी के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि स्कूल पाठ्यपुस्तकों को इन मुद्दों को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना चाहिए, और संरचनात्मक चुनौतियों और अनुशासनहीनता के आरोपों के बीच अंतर करना चाहिए।

यह विवाद यह भी दर्शाता है कि शैक्षणिक सामग्री और न्यायिक निगरानी के बीच संवेदनशील संबंध बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अदालतें ऐतिहासिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वायत्तता का बचाव करती रही हैं, वे तब हस्तक्षेप करती हैं, जब संस्थागत अखंडता को खतरा महसूस होता है।

यह विवाद, जवाबदेही और विश्वसनीयता के बीच तनाव को दर्शाता है। न्यायपालिका, जैसी सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, आलोचना से परे नहीं है। फिर भी उस आलोचना का ढांचा, विशेष रूप से शैक्षणिक सामग्री में, सार्वजनिक विश्वास के लिए, परिणामस्वरूप हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मजबूत टिप्पणियाँ इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्रतिष्ठा का यह क्षरण केवल एक अलग आलोचना नहीं, बल्कि संस्थागत वैधता के बड़े कथात्मक संघर्ष का हिस्सा हो सकता है। एनसीईआरटी इस सामग्री को कैसे संशोधित करता है, और क्या यह घटना पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक संस्थाओं को प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की ओर अग्रसर होती है, यह तय करेगा कि विवाद शांत होता है या फिर आलोचना की सीमाओं पर एक बड़ी बहस शुरू होती है।

होली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिल्ली और उत्तर रेलवे के अन्य स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे नियमित ट्रेन में कन्फर्म टिकट लेने से वंचित लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी।

सिम के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दूरसंचार विभाग ने गाइडलाइन के मुताबिक कंपनियों को नियम लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया था। इसका मतलब है कि डेडलाइन 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी और 1 मार्च 2026 से सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को सिम-बाइंडिंग सिस्टम लागू करना अनिवार्य होगा। मोबाइल एप के साथ ही वेब और डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी नया नियम लागू होगा। अगर आप व्हाट्सएप वेब या डेस्कटॉप पर लॉगिन करते हैं, तो हर छह घंटे में ऑटो लॉग-आउट हो जाएगा। दोबारा इस्तेमाल के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर लॉगिन करना होगा। नए नियम के तहत जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना है, वही सिम कार्ड आपके फोन में एक्टिव रहनी चाहिए। अगर वह सिम फोन से हटा दी जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, तो एप उस डिवाइस पर काम करना बंद कर देगा।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908